



सरकारी विलेखन
संख्या ४४७८५

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. १९०]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर १, १९८०/आश्विन ९, १९०२

No. १९०]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 1980/ASVINA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न अंतीमी तर्ज से जिससे कि यह अलग सकलन की रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

आणिंद्य भंत्रालय

(आयात व्यापार मियाचण)

सार्वजनिक सूचना सं. ३७ आई टी सी (पी एन)/८०

नई दिल्ली १ अक्टूबर, १९८०

विषय—विदेशी आधिकारिक राज्याग्र निधि (आई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए २७ विलियन येन ऋण के अधीन माल का आयात और सेवाओं के समन्वय में लाइसेंस दर्ते।

विदेशी आधिकारिक राज्याग्र निधि (आई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए २७ विलियन येन ऋण के अधीन टेलिकम्पनिवेशन परियोजना, (१) के लिए माल के आयात और सेवाओं के समन्वय में आयात लाइसेंस दर्ता के नियमन को नियन्त्रित करने वाली गति जो इस सार्वजनिक सूचना में दी गई है नामांगी नियन्त्रित की जाती है।

[मिनिम स० आई पी मा २३/१०/८० में जारी]

मणि नागर्यण न्वामी मुख्य नियन्त्रक आयात नियन्त्रित

आणिंद्य विभाग की सार्वजनिक सूचना संख्या ३७ आई टी सी (पी एन)/८०, फिलाक १-१०-८० कर परिशिष्ट।

विदेशी आधिकारिक मत्याग्र निधि (आई सी एफ) द्वारा प्रदान किए गए २७ विलियन येन ऋण के अधीन टेलीकम्पनिवेशन परियोजना (II) के लिए माल के आयात और सेवाओं के समन्वय में लाइसेंस दर्ते।

एच-१-सामन्य गति

१ (१) महानिवेशन डाकतार की दूर सचार परियोजना की आयात आवश्यकताओं के वित्तदान ने लिए आपान की विदेशी आधिकारिक मह-

याग निधि (आई सी एफ) द्वारा प्रदान किया गया २७ विलियन येन का ऋण विकासीयात देणे के लिए द्युता है। तबनुसार इस श्रेष्ठ दे अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएँ और सेवाएँ आपान और अनुवन्ध-१ की सूची में उद्धृत मध्ये दर्शों से आयात की जा सकती है। ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्थान देश होंगे।

१ (२) श्रेष्ठ के अधीन केवल उन्हीं मध्ये और उसी मूल्य के लिए लाइसेंस जारी किये जा सकते हैं जिनके लिए महानिवेशन तकनामी विकास/पूजीगत माल नमिनि द्वारा विशेष रूप से नियासी कर दी गई हो। इस श्रेष्ठ के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सो) वा मूल्य ३,००० मिलियन (लागत बीमाभासा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रूपये में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा-भूलक) द्वारा अधिसूचित विनियम दर और आयात लाइसेंस जारी करने की निधि वा प्रचलित दर और मुख्य नियाक, आयात नियर्यत द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं. ७८-आई टी सी (पी एन) ७४ विनांक ६ जून १९७४ के पेरा २ के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतिक दर पर निर्धारित किया जाएगा। जिसमें यह भी उल्लेख है कि सीमा भूलक आयाती और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत आयाती आयात लाइसेंस (सो) में विनिविष्ट मुद्रा विनियम दर पर लाइसेंस मूल्य के नाम डालेग। लाइसेंस पर एक शीर्षक 'आयाती धन ऋण मूल्य आई टी-५ होगा। प्रथम और द्वितीय प्रथम के लिए लाइसेंस में 'एस/जे एन' काढ़ होगा। महानिवेशन डाक तार की आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियन्त्रक, आयात नियर्यत के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा। जिसकी एक प्रतिधिकृत महानिवेशन, आधिकारिक कार्य विभाग (आपान अनुभाग) का पृष्ठांकित का जानी चाहिए।

१ (३) नागर-बीमा भाड़ा के आधार पर केवल महानिवेशन डाकतार का नाम में ही लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

(4) महानिदेशक डाक तार की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक भाग्यात लाइसेंस इस फोडिट के अधीन जारी किये जा सकते हैं। लेकिन कुल मूल्य 3,000 मिलियन (लागत बीमा भाड़ा) ये ने अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर देखा (1) में कहा गया है।

(5) भायात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि महानिवेशक डाक तार द्वारा भावेदन करने पर 31-12-84 तक दी जा सकती है। इससे भ्रागे की वृद्धि यदि कोई हो तो, भायिक कार्य विभाग (जापान अमूमाग) को सेवा जानी चाहिए।

(6) केडिट के मध्यीन वित्तान किए जाने वाले प्रायात, प्रायात लाइसेंस से संलग्न माल और सेवाओं की सूची जोकि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित हो, तक प्रतिबंधित है।

(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेण्य की अनुमति आयात-साइर्स के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकार्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अधिकार्ता को भारतीय स्पष्ट में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान साइर्स मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए साइर्स पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

(8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए, और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की प्रवृत्ति के भीतर प्रार्थिक कार्य विभाग (आपात अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए । भाड़ा और बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय संघर्ष में भारत में किया जाएगा । "पक्के आदेशों" का प्रर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस-धारी द्वारा दिए गए उन काय आदेशों से है जो या सो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो या भारतीय आयातक या विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित काय संविदा हो । विदेशी संभरकों के भारतीय प्रधिकरणों के आदेश या ऐसे भारतीय प्रधिकरणों द्वारा "पुस्तिकरण आदेश स्वीकार्य" नहीं है ।

1 (8) चार महीनों की अवधि के भीतर बैंकों की इस रस्ते का तब तक प्रत्युपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि लेनेके के पूर्ण वस्तावेज आयात लाइसेंस आरो होने की तिथि में चार, महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंक्स्ट्र्यू इ० १ अनुभाग को नहीं पहुँच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1 (8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं रिपैज जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आवेदन क्यों नहीं रिपैज जा सकते इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसदात्री को आयात लाइसेंस को मम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को अस्तुत कर देना चाहिए। आवेदन देने की अवधि में बृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पाकता के आधार पर विचार किया जाएगा वे प्रधिक से प्रधिक चार महीनों की ओर अवधि के लिए बृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि बृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से ८ महीनों से प्रधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निररपाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई विल्सन बॉल बेंजे जाएंगे जो कि ऐसी बृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पाकता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसदात्री को प्रेरित करेंगे।

साइंसेसधारी शारा लाइसेंस प्राधिकारियों में केवल ऐसी कृति प्रदान करने वाला एक पक्ष प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी, आयात साइंसेंस के अधीन किए, गए संभरण ठेकों के संबंध में ऐसे गारंटी साखिपत स्थापित करने के लिए प्राधिकारियत तुल्य नप्या जमा करने की स्वीकृति शावि की मनविधायों की प्रनमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से चार महीने के भीतर सभी भुगतान प्रवर्श्य पूर्ण कर देने चाहिए । माल के पोत लदान पर अलग-अलग भगतानों को व्यवस्था होनी चाहिए । इनमें नक्श आधार

पर अरथात् पोतलदान वस्त्रावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक का किसी भी किस्म की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए टेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए।

“माला पत्र की प्राप्ति के बाद महीने परन्तु अधिक से अधिक के अन्त तक पूर्ण किया जाता है।”

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-84 के बाद की न हो।

लक्षण-2-संमरण टेके का समझौता करते समय ल्याप्टो में रखी जाने वाली विशेष जांचें

2(1)(क) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन मे (येन की भिन्न के बिना) प्रभिष्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय प्रभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो सो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रूपा में चुकाना चाहिए । भारतीय रूपा या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में प्रभिष्यक्त नहीं होना चाहिए । कल्य आदेश और संक्षरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश के बल प्रयोजी में होना चाहिए ।

2 (2) श्रोईसीएफ० येन केडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाएँ प्रदिपाप्त करने के लिए विस्तृत मिवेंश अनुबंध-2 में विए गए हैं। लेकिन माध्यारणतया, माल और सेवाएँ की प्रदिपाप्त श्रोपारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविदा के माध्यम से की जानी चाहिए और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:—

(क) भोली लगाने के लिए नियंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचालित होने वाली कम से कम एक अखंकार में विस्तृप्त करने पड़ेगे।

(ख) बोली के बाण्ड या बोली लगाने की गारमटी सामान्य आवश्यकता है परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना काहिए कि उचित बोली लगाने आवेद ल्होत्साहित हो जाए।

(ग) बोली खुल जाने के बाद असफल बोलीकारों को यथा शीघ्र बोली बांध या गारमिया रिहा कर देशी छाहिं।

2(3) जिन मामलों में ग्रोपचारिक खासी प्रत्यरूपीय संविदा उचित न हो वहां निधि निम्नलिखित बैंकिस्पक क्रियाविधि अपनाएगी:—

(क) जहाँ आधातक के पास विश्वसनीय कारण हों या अपने उपस्थिर का उचित मानकीकरण रखता हो ।

(स्थ) जहां पर पाल संभरको की संख्या सीमित हो ।

(ग) जहां प्रशिक्षणी में शामिल धनराशि हत्ती कम हो कि विदेशी फर्म स्पष्ट रूप से रिलायरी न ले या यह कि भ्रौपकारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय संविधा के कायदे शामिल प्रशासकीय भारत से महत्वपूर्ण हों।

(घ) उपर (क), (ख) और (ग) के अतिरिक्त जहां निधि औपचारिक खुली अन्तर्दिलीय निविवा का अनुकरण करना अनुचित समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया को अनुपयुक्त समझे उत्तराधरणार्थ आपात अधिकारियों के मामले में।

ऊपर संकेतित मामलों में निम्नलिखित अधिप्राप्ति प्रतिया इस दृग् से प्रपत्ताई जाए जिससे कि जहाँ तक उचित हो पूर्ण संभाव्य सीमा तक घैरुपारिक छली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अन्तराल हो सके:—

(1) श्रीपात्रारिक चूनिया अस्तराष्ट्रीय निविदा करना

(2) अनोपचारिक अनन्तर्द्वय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति ।

(3) एक संभरक से भ्राता करना ।

५-महानिवेदक डाक तार को विशेष कारण/प्रोत्तित्य अताने वाली कालियों के सूत्याकृत और तुलना पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जिस पर न्यूनतम भूत्याकृत बोली आधारित हो। और इनकी तीन प्रतियों के साथ अली विकल्पण विवरणी शीट, दस्तावेजी माड्यो महिला विकल्प कोई हो। हाँ विन मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई विली को भेजनी चाहिए जो विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (आई सी एफ) से उमका आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें। यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्या मंत्रिवाच, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) (जापान अनुभाग) द्वारा श्रो०५०८००५० को केवल नवी अधिसूचित विया जाएगा जबकि रिपोर्ट आदि का आई०८००५० से अनु-मोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

२(4) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंकों द्वारा १९७९-८० के लिए और ई सी एफ येन क्रेडिट (परियोजना महायाता) सं० आई ई पी-५ के अधीन आंते गा, अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका अंग नीचे खण्ड ६ में दिया गया है।

२(5) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदित प्राप्त कर लेना चाहिए।

२(6) संभरक की प्राप्ति

संभरक पात्र लोत देशों का नागरिक या पात्र लोत देशों के नागरिकों द्वारा यथार्थरूप से शासित वैध व्यक्ति होगा। उसे निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी पड़ेगी:—

(क) मात्र लोत देशों के नागरिकों द्वारा अधिकतर प्रभिदत्त शेयर रखे जाएं।

(ख) अधिकतर पूर्ण कालिक निवेशक पात्र लोत देशों के नागरिक हों।

(ग) गेमे वैध व्यक्ति पात्र लोत देशों में पंजीकृत हों।

२(7) संविदा में धोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पालता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा:—

“मैं, अधोहस्ताक्षरी एकद्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभावित किया जाने वाला माल”..... “मैं (पात्र लोत देश) उत्पादित है।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विज्ञास के अनुसार अपात्र लोत देशों में आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुमार ३०% से कम है:—

आयातित लागत बीमा-भाड़ा मूल्य आयातित शुल्क $\times 100$ ”

संभरक का जहाज पर निषुल्क मूल्य

ओर

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, एकद्वारा सत्यापित करता हूं कि—
(पात्र लोत देश का नाम) _____ (काल्पनी का नाम)
सम्भाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र लोत देशों के नागरिकों द्वारा नियंत्रित है।

२(8) अपात्र सूत्र देशों से अनुमेय आयात

जिस बम्बुओं में अपात्र लोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका विस्तार किया जा सकता है बताते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुमार मदबार आधार पर आयातित भाग ३०% से कम हो:—

आयातित लागत बीमा + आयात शुल्क

भाड़ा मूल्य

$\times 100$ ”

संभरक का जहाज पर निषुल्क मूल्य

बष्ट-३-संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

३(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विणेप रूप से समाविष्ट होने चाहिए:—

(क) ठेकों की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (आईसीएफ) के बीच दूर संचार परियोजना

(2) के लिए येन क्रेडिट आईसीपी-५ (परियोजना सहायता) से सम्बन्धित ८ मई, १९८० को हुए अण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (आईसीएफ) के बीच येन क्रेडिट सं० आईसीपी-५ से सम्बन्धित ८ मई, १९८० को हुए अण समझौते के अन्तर्गत बैंक आफ इण्डिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और वस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होना जो एक और भारत सरकार द्वारा और तूसगे और आईसीएफ द्वारा येन अण के अधीन अपेक्षित हों।

(घ) २(7) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में)

३(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के सम्बन्ध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इन उद्देश के लिए यह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल माल की सुपुर्देशी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पोतलदान से कम से कम ५ मप्ताह पूर्व दूतावास को सूचना देना जिसे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहाँ भारतीय आयातक इच्छुक हो, सूचना की इच्छावधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक का प्रत्येक पोतलदान के पश्चात् आवश्यक और देने हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

बष्ट-४—विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (श्रो०५०८००५०) द्वारा ठेकों का अनुमोदन

४(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर महानिवेदक डाक एवं तार और विदेशी सम्भरकों दोनों द्वारा विविधत हस्ताक्षरित ठेकों की चार प्रतियों जो विदेशी संभरक द्वारा लिखित में पुष्ट विवेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों, संगत वैध आयात लाइसेंस की २ फोटो प्रतियों महिन, जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई विली को भेजनी चाहिए।

(2) उपर्युक्त कियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विवेशम्बु के लिए अनिवार्य आशोधमालों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, तार संचार परियोजना (2) के लिए येन क्रेडिट सं० आईसीपी-५ (परियोजना

सहायता) के अन्तर्गत विस्तारन करने के लिए विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (आई सी एफ) की संविधा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की अवस्था करेगा।

खण्ड-5—विदेशी संभरकों को भूगतान-सात्त्व-पत्र क्रियाविधि

5(1) विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (आई सी एफ) से बैंकों के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग द्वारा सम्प्राप्ति देखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद महानिदेशक, डाक एवं तार के प्राधिकृत बैंकर की अपृष्ठ कार्य विभाग द्वारा सम्प्राप्ति देखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद महानिदेशक, डाक एवं तार के प्राधिकृत विभाग की सहायता देखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सीएए कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यूसीओ बैंक विलिंग, संभव मार्ग नई शिल्पी को अनुबन्ध 3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करता चाहिए। सीएएए अण्डे ५ अनुबन्ध-४ के रूप में संलग्नक प्रपत्र में एक प्राधिकार पत्र भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को अनुबन्ध-५ (वास्तविक आयातों के लिए) या अनुबन्ध-६ (सेवाओं के लिए) के रूप में संलग्नक प्रपत्र में सम्बन्धित विदेशी संभरक के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए जारी करेगा। प्राधिकार पत्र की प्रतियां (विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि) (आईसीएफ), भारतीय दूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी।

5(2) प्राधिकार-पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक टोकियो अनुबन्ध-५ (आयातों के लिए लागू होता है) या ६ (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार सम्बन्धित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय याकृपन की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि (आईसीएफ) भारतीय दूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता देखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, को भी भेजेगा।

सी ए ए ए से प्राधिकार-पत्र के आधार पर साखपत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविधा संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे ही सभी प्राधिकार पत्र/साख-पत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होती।

5(3) माल का पोत लदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भूगतान के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए हों तो बैंक आफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साखपत्र खोलने, रख-रखाव और उनके प्रचालन के मारे खर्च विदेशी संभरकों के लेखे में लिए जाएंगे। इसलाएं, भारतीय बैंक, टोकियो विदेशी बैंक से हन सभी खर्चों की बसूली करेगा, सौदे से सम्बन्धित दस्तावेजों को भेजने की अवस्था करने के लिए खर्च और अन्य प्रासंगिक खर्च भी संभरक द्वारा उठाए जाएंगे।

भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा संभरक को माल के जहाज पर निःशुल्क भूगतान की तारीख और आईसीएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख के बीच अन्तराल के लिए भारतीय बैंक 25-३-१९८० को भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ उनके द्वारा किए गए समझौते के नियम एवं शर्तों के अनुसार व्याज की बसूली करेगा और भारतीय दूतावास टोकियो से उसकी प्रतिपूर्ति करवा लेगा। जापान में भारतीय दूतावास योधारा इस व्याज के भूगतान से हुए खर्च [खण्ड ६ (4) के अनुसार] डाक एवं तार विभाग से बसूल किए जाएंगे।

खण्ड-6—हवया निषेक करने के लिए उत्तरवायित्व

6(1) भारतीय बैंक टोकियो संगत प्राधिकारपत्र के परिशिल्षण में संक्षित अनुसार महानिदेशक, डाक एवं तार के प्राधिकृत बैंकर की अपृष्ठ कार्य विभाग द्वारा सम्प्राप्ति देखा तथा लेखा और बैंकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि महानिदेशक, डाक एवं तार ने जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, लॉन्ग हजारी, विल्ली में रुपया निषेप कर दिया है। विदेशी संभरक की दिए गए येन भूगतान के समतुल्य रुपया सार्वजनिक सूचना सं०-७४ आईटीसी (पीएन)/७४, दिनांक ३१-५-१९७४ में निर्धारित तरीके से भारत सरकार के नेत्रों में जमा किया जाएगा। विदेशी संभरक को किए गए येन भूगतान के समतुल्य रुपया की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाले विनियम की दर भूगतान की तारीख को लागू विनियम की वह मिशन वर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं०-१०९-आईटीसी (पीएन)/७४, दिनांक ३-८-७४ और सं० ८ आईटीसी (पीएन)/७६, दिनांक १७-१-१९७६ में निर्धारित तरीके के अनुसार महानिदेशक की दिए गई होती जो भूगतान की मात्रायम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मद्दा विनियम नियंत्रण परिस्थितों के माध्यम से मरकार समय-समय पर घोषित की गई हो। जिस लेखा गीर्य में उपर्युक्त रुपया निषेप किया जाएगा वह “के डिपोजिटस एण्ड एडवांस-४४३ सिविल डिपोजिटस-डिपोजिट्स फार परचेज एटस्ट्रा एग्रो, परचेज एण्ड फ्रेड्स्टैम। लौन एग्रीमेण्ट लौन फोम दि गवैनमेंट आफ जापान २७ विलियन येन फ्रेड्स्टैम सं० आईईईपी-५ फार टेलिकम्प्लिकेशन प्रोजेक्ट(२)” होना चाहिए। किन्तु ३१-५-१९७४ की उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित व्याज खर्च और निषेप की गणना से सम्बन्धित व्यवस्थाएँ लागू नहीं होती क्योंकि कन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किए गए आयातों के सम्बन्ध में कोई भी व्याज खर्च बसूल नहीं किया जाता है।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नीस हजारी, विल्ली में सरकार की भाव में सार्वजनिक सूचना भूम्य-१४-आईटीसी (पीएन)/६८, दिनांक ३०-८-१९६८, सं० २३३ आईटीसी (पीएन)/६८, दिनांक २-४-१०-१९६८ सं० १३२ आईटीसी (पीएन)/७१, दिनांक ५-१०-७१, सं०-७४ आईटीसी (पीएन)/७४, दिनांक ३१-५-७४ और सं० १०३ आईटीसी (पीएन)/७६ दिनांक १२-१०-७६ में व्यानिर्धारित तरीके में जमा होनी चाहिए।

6(3) भारत सरकार वित्त भवानीय आर्थिक कार्य विधान द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सत्र दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अप्रिवर्तन धनराशि जेवर खर्चों को निर्भत भेजेगा जो विन भवानीय (आर्थिक कार्य विधान) द्वारा मार्गी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भारत समय अपारतकों/उनके बैंकरों को द्वारा बात का मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० १०३ आईटीसी (पीएन)/७६ दिनांक १२-१०-७६ के माध्यम से जानी जानी वाली सार्वजनिक सूचना सं०-१३२-आईटीसी (पीएन)/७१, दिनांक ५-१०-१९७१ के वैरा २ में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं०-७४-आईटीसी (पीएन)/७४, दिनांक ३१-५-७४ में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम “धन परिवर्तन और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण वैरा” में निरापद्धत रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। अजाना चालान में निर्धारित वैरा और निरपवाक रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

- (क) विल मंत्रालय के प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक;
- (ख) येन मुदा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निषेप किए जाने हैं;
- (ग) विदेशी संभरक का भूगतान करने की निधि।

उम्में पश्चात् सी ए ए ए द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संबंध देते हुए और बीजक तथा पौत्र परिवहन दस्तावेजों को संक्षिप्त करते हुए

ਖੜਾਨਾ ਚਾਮਾਨ ਹੱਥਧਾ ਜਮਾ ਕਰਨ ਬਾ ਸਾਕਧ ਦੇਤੇ ਦੁਹ ਪੰਜੀਝੂਨ ਢਾਰ ਦੁਆਗ
ਮੰ ਇ ਗ ਗ ਕੀ ਭੇਜਾ ਜਾਨਾ ਆਹਿਏ।

टिप्पणी - भारत में श्रावात्मक के बैक का यह मुनिश्चित्त अरता चाहिए विस्तृप्त या निक्षेप भारतीय बैक, टाकिया में अद्वायी की मूर्चना और अपरिवर्तनीय पात लादन दस्तावेजों की प्राप्ति वे १० दिनों के भीतर निगमपाद रूप में किया जाता चाहिए और यह कि इसके तत्वावधार सांपण, विल मन्त्रालय (प्राथित धार चिभाग), नई दिल्ली का सचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में गम्भीर भारतीय बैंक का साइमेंग की मुद्रा विनियमन नियक्षण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठावन करना चाहिए और अपार्क्शन 'एम' प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आपके अस्त्रै व्यापार का भेजना चाहिए।

भारतीय फ्रूटावास टाकिया द्वारा भारतीय बैंक, टाकिया का किए गए ल्योज आदि के आधार पर येत भूगतान के समतुल्य रूपां की गणना भी उपर्युक्त खण्ड-6 की फाइलका 6(1) मे उत्तिष्ठित मरीक स की जाएगी और उसे मध्य लक्ष्य श्रीधरकारी विदेश मन्त्रालय के नाम मे रमा किया जाए। जिसक प्रयोगनाथ से गण एवं एवं ग उचित बौजक जारी करेगा।

खण्ड 8- लिखित व्यवस्था

8(1) अत्यात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्ट

आयातक का पत्र पदान और उसके अधीन किए गए भूगतान और शब्द धनराशि व भार में साक्षरपत्र आयत के बाद एक मार्गिक रिपोर्ट सहीयता लेखा था १२ क्षा नियन्त्रक आर्थिक वायं विभाग, वित्त भालालय यू०सी० और० बैंक बिलिंग मस्त्र भार्ग, नई विल्लों का भेजनी चाहिए।

8 (2) सम्भारकों को विशेष शर्तों के बारे में प्रधिसचित करना

याइमेसाधारी को आवात लाक्षसेस में विण पाय किसी उन चिरोष उपसंधियों से सभरक ना अवगत करा देना चाहिए जो माल का लाने वे जाने में सभरक पर प्रभाव डालती हो ।

8(3) विवर

यह समझ सेना आशिंग कि लाइसेंस और सभरको के बीच कोई विवाद उठेगा ता उसके लिए भारत भगवार कोई उत्तरदायित्व नहीं रखें। भारत में वैक टाइथ। द्वारा किंग गण भगवान में पहले सभरव द्वारा पूरी व जाने वाली शर्त अनुबंध ३ में “भगवान की शर्त” के अन्तर्गत अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान में सम्बद्ध व्यवस्थाएं शार्मित होनी चाहिए।

8 (4) भवित्वा अनुवेश

आयान लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ आड़े होने वाले किसी मामले या गर्भी मामलों से सम्बन्धित या जापानी प्राथिकारियों के साथ थेन क्रेडिट समझौता (पण्यवस्तु भव्यता) व अर्धान मर्मी आक्षण्ण को पूर्ण करने के लिए सारल रारम्भ इक्वारा समय-समय पर जारी बिंग गए नियोजी अनुदेशा या आदेशा का लाइसेंसधार्ता को तुरन्त पालन करना होगा ।

8(5) अतिक्रमण दू. जहलभास

उपयुक्त लाइज़ों में स्थिर की गई शर्तों के अधिकारण या उल्लंघन करने पर आयत निर्यात (नियमण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जा रही।

8(6) अनुद्धरणों को सख्ती

पात्र सीन देशो की सूची

२ अनुबन्ध २	अधिकारित के लिए मुख्य मार्गदर्शन
३ अनुबन्ध ३	प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए अनुबन्ध
४ अनुबन्ध ४	प्राधिकार-पत्र का प्रपत्र
५ अनुबन्ध ५	साक्ष-पत्र का प्रपत्र (वास्तविक भायाता के लिए लागू)
६ अनुबन्ध ६	भास्त्र-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

अनिवार्य १

ਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਂਗੋ ਜੀ ਸਚਿ

(क) विकाससंगीत वेश तथा उसके भाव
 (क-1) घो धी ई सो से मिल विकाससंगीत वेश
 (ख) विकाससंगीत वेश तथा उसके भाव
 (ख-1) भास-घोपी-ई-सो विकाससंगीत वेश

1 अफ्रीका, उत्तरी सहारा

मिस्र
मोरोका
तनीशिया

१ अक्षीका, वक्षिणी सहारा
 अंगीला
 वात्सवाना
 अरन्डी
 कीमरन
 केप अडी द्विपसमह
 कन्द्रिय अक्षीका गणतन्त्र
 चाह

कमारो द्वैपसमूह
हथियापा
जाम्बवा
घाना
गिरी
आहवरी वास्ट
कीनिया
लेसोथो
साइरिया
मालायासी गणतन्त्र
मलाबी
माली
मार्कितानया मार्कशम
मुजास्सीक
नाइरा
पुतेंगाली गिना
रियुकियन
राइशिया
खान्दा
मेट हेमिना भौर डेप (साम्रोदोम भौर प्रिन्साल
सेनगाल
मेजिलिम
सियरा लिंग्वोन

सोमालिया	इजराइल
सूडान	जोर्डन
स्वाझीलैंड	लेबान
टेरी भाष्यक और इत्साह	ओमन
टोमों	सिएप्राई भर्त्य गणतंत्र
युगान्डा	यूनाइटेड भर्त्य प्रभिरात
तजानिया गणतंत्र संघ	यमन भर्त्य गणतंत्र (3)
अपर बोल्टा	यमन जनशादी ई.०प्र० (4)
जाइरे गणतंत्र	
जाम्बिया	
3. अफ्रीका उत्तरी और केन्द्रीय	6. दक्षिणी एशिया
बेहुमत	अफगानिस्तान
बारबोडोज	बांगला देश
बेलाइज	भूटान
बरुज़ा	बर्मा ।
कोस्टारिका	भारत
कनूबा	मालदीप
होमिनिकन गणतंत्र	नेपाल
एस लाइबेरोर	पाकिस्तान
गुआडलोप	भ्रीलंका
ग्वाटेमाला	
हंती	7. सदूर पूर्वी एशिया
होण्डूरस	बहूली
जेमैका	हांगकांग
मार्टिनिक	खमेर गणतंत्र
मेक्सिको	कोरिया गणतंत्र
नीदरलैंडस एनडिसीज़	लाओस
निकारागुआ	मकान्द्रो
पनामा	मलेशिया
सेन्ट पियरों और मिकेलोन	फिलिपाईन
ट्रिनिडाड और टोबॉगो	सिंगापुर
बेस्ट इण्डोन (शाका) एस०प्र०ई०	ताइवान
(क) सम्बन्धित राज्य (1)	थाइलैंड
(ब) भारित (2)	तिब्बत
(1) पहले स्टेटी जिनी के प्रदेश, फरनेन्डो वो द्वीप समूहित	वियतनाम गणतंत्र
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—	वियतनाम जनशादी गणतंत्र
मसेन्ट, ट्रिस्टन डा इन एंसोसिविट्स, नाइट्रिंगल गण।	
(3) मुख्य द्वीप समूह, भर्बी, बोलाहरे, क्यूराकाओं लाहा, सेन्ट भारटिन (दक्षिण भाग)	
4. दक्षिणी अमरीका	8. ओसिनिया
अर्जेन्टीना	कोक द्वीप समूह
बोलिविया	किज़ी
ब्राजील	गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
चिली	कोसिसो पोलिमेशिया (5)
कोलम्बिया	नौर
फार्फ्लैंड द्वीप तम्बू	न्यू कासेडोनिया
फ्रांसीसी जिनी	न्यू हेसिसेस (वि और फ्रैं)
गुयाना	हिन्दू
पाराग्वे	पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त
वीरू	राज्य (6)
सूरिनाम	पायुमा न्यू जिनी
उरुग्वे	शोलामन द्वीप समूह (वि)
5. मध्य पूर्वी एशिया	टोमों
बहरीन	बालिस और कुतुना
	पश्चिमी साम्राज्य
	9. मूरोप
	साइप्रस
	जिम्बाल्टर

क्रीक	बाण्ड 3. 01	दिशिप्लिकरणों का स्पष्टीकरण
मास्टा	बाण्ड 3. 05	मापदण्ड
लैंग	बाण्ड 3. 06	बाण्ड नामों का उपयोग
तुकी	बाण्ड 3. 07	मंचिवादीों के अन्तर्गत व्यय
यूनोस्कारिया	बाण्ड 3. 08	बोलियों का मूल्य
(1) मुख्य द्वीप एनिटूबा, डोमिनिका, प्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफेरी)	बाण्ड 3. 09	मंचिवादी मूल्य
नेविल अग्रहाना, सेन्टलुसिया और सेन्ट क्रिस्टोफेरी	बाण्ड 3. 10	मूल्य संबंध धाराएं
(2) मुख्य द्वीप : मोनेसरल, मेपान, नक्क और काइकोस और त्रिटिम वर्तिम द्वीप समूह	बाण्ड 3. 11	प्रग्राम भुगतान
(3) प्रजासाम, बदल, कुजाइरह, रास अल मेमाह, शरजाह और उम अल फर्दिन	बाण्ड 3. 12	गारन्टीयों भित्तिवान बांड और रोक रखा गया धन
(4) प्रदम और विभिन्न मुस्लिम और अमेरिक समूह।	बाण्ड 3. 13	बीमा
(5) तोसापटी द्वीप समूह (ताहिरी महित) को शामिल करते हुए, अस्ट्रेल द्वीप समूह, ट्रामोट, जामिन्दर पुण और मालेसिया द्वीप समूह।	बाण्ड 3. 14	चुकाई गई क्षति और बोल्स धाराएं
(6) वैसिकिक द्वीप समूह का द्रस्ट प्रवेश : कारोबीन द्वीप समूह, मार्थल द्वीप समूह और ऐरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)	बाण्ड 3. 15	वाइकार स्थितियां (कोर्स मेज्यूर)
(क2) बॉ० धॉ० ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश	बाण्ड 3. 16	भावा की व्याख्या
प्रस्तीरिक	बाण्ड 3. 17	विवादों का निपटारा
बीलिंगिया	बाण्ड 4. 01	बोली बौलना, मूल्यांकन और संविदा प्रदान करना
लीबियाई अरब गणराज्य	बाण्ड 4. 02	बोली आवंतित करने और बोली जगते के बीच का समय
गेबान	बाण्ड 4. 03	बोली जोकरे की क्रियाविधि
नाइजीरिया	बाण्ड 4. 04	बोलियों का स्पष्टीकरण या परिवर्तन
इज्बोर्ड	बाण्ड 4. 05	क्रियाविधि गोपनीय रखना
बेन्जुला	बाण्ड 4. 06	बोलियों का परीक्षण
ईरान	बाण्ड 4. 07	बोलियों का मूल्यांकन तका तुलना
ईराक	बाण्ड 4. 08	बोलियों को रह करना
कुर्दी	बाण्ड 4. 09	मंचिदा प्रदान करना
कातार	बाण्ड 5. 01	मलाहकारों के उपयोग के लिए मार्ग दर्शन
सउदी अरब	बाण्ड 5. 02	मलाहकारों की स्वतंत्रता
अबुधाबी		मलाहकारों का चयन
इस्लामिया		संस्कृत वस्तु :—पाल जोत देश
		कृष्ण के अन्तर्गत बाल प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शन

अनुच्छेद-2

अज्ञ के अधीन अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन
विषय बोली की तालिका

अनुच्छेद संख्या	शीर्षक
अनुच्छेद 1	मामास्य
खण्ड 1. 01	प्रस्तावना
खण्ड 1. 02	प्रोप्रोलिक बूले अम्तररफ्टीय निविदा करने से भिन्न क्रियाविधि
खण्ड 1. 03	संविदादीों की किस्म और आकार
अनुच्छेद 2	विज्ञापन और इसमें पूर्व की शर्तें
खण्ड 2. 01	विज्ञापन
खण्ड 2. 02	बोली लगाने से पूर्व की शर्तें
अनुच्छेद 3	बोली लगाने वाले वस्तावेज
खण्ड 3. 01	निष्ठि के लिए मन्दर्भ
खण्ड 3. 02	बोली बाण्ड अप्लाया गारन्टीया
खण्ड 3. 03	संविदा की शर्तें

अनुच्छेद-2

तालिका

खण्ड 1. 01 प्रस्तावना

(क) ये निर्देशन दिक्षु उत्त नियमों की बताते हैं जो कि विवेकी आर्थिक सहयोग निष्ठि (इसके बाब निष्ठि कहलाए) उस परियोजना के विकास के लिए माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए सामान्यतः लागू करती है जिसके लिए निष्ठि अपने ज्ञान द्वारा पूर्ण रूप से अधिक आर्थिक रूप से वित्त प्रदान करती है।

(ख) निष्ठि के ज्ञान की रकम की मितव्यता, वस्तावा और उन देशों के बीच जिना भेदभाव की जावना को विशेष रूप से ध्यान दे रखते हुए उपयोग करना होगा जो कि उपर्युक्त माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए वाल और सेवाओं का आर्थिक और वक्षतापूर्ण अधिप्राप्ति के लिए सबसे अच्छा साधन है। प्रतः निष्ठि अपने ज्ञानी से साझेदारणः अपेक्षा करता है कि वह औपचारिक बूली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से माल तथा सेवाओं को प्राप्त करे।

(ग) निधि द्वारा वित दान की गई किसी विशेष परियोजना लिए इन निर्देशन विन्दुओं का लागू होता, बोली लगाने के वस्तविक और अधिकारियों की कियाविधियों जिस सीमा तक निधि द्वारा यह सुविधाजनक करने के लिए प्रतीक्षित के अधीन है कि वे इन निर्देशन विन्दुओं के अनुसूची हैं पात्र सोत देश और आगाम लोत द्वारा भी अनुमेय प्रायतों के लिए प्रायधार उन पर्योजना के लिए निधि द्वारा प्रदान किए गए अर्थ के सविया सम्बन्धी दस्तावेजों में निर्धारित लिए जाएं।

(घ) किसी भी परियोजना पर माल और सेवाओं की अधिकारियों के लिए अलिम उत्तराधिकार परियोजना के स्वामी पर होता है। वृक्ष स्वामी प्रायः कहीं भी होता है इसलिए इन सार्व निर्देशन विन्दुओं में कहीं शब्द का प्रयोग मालिक के लिए भी किया गया है। परियोजना के लिए प्रदान किए जाने वाले साल और सेवाओं के लिए बोली लगाने वालों के विषय में कहीं के अधिकार और दायित्व कहीं द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों द्वारा सामिल किए जाते हैं इन सार्व निर्देशन विन्दुओं द्वारा नहीं, ये निर्देशन विन्दु केवल कहीं और निधि के बीच क्षमा सम्बन्ध हैं इससे सम्बन्धित है।

खण्ड 1.02 ओपचारिक बोली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न कियाविधियों

कुछ ऐसी विशेष परिमितियों हो सकती है जिनसे ओपचारिक बुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा उपर्युक्त न ठहरे और निम्नलिखित मामलों में निधि अन्य दूसरे तरीके अपनाएँ—

(क) जिस मामले में कहीं के पात्र अपने उपस्कर का एक उचित नामकीकरण कायम रखने के लिए विश्वसनीय कारण हो,

(ख) जिस मामले में पात्र सम्भरकों की संख्या सीमित हो जैसे विद्यमान उपरकर के लिए फालन्दू पुर्जी की संख्या,

(ग) जिस मामले में अधिकारियों के लिए लगी दुई धनराशि इनी कम हो कि विवेशी पारिया स्पष्ट रूप से इच्छुक न हो या यह कि अन्तर्राष्ट्र भार प्रणालीय भार ओपचारिक बुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के लाभ से मक्तव्यपूर्ण हो।

(घ) जिस मामले में उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के अनिवार्य निधि ओपचारिक बुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की कियाविधियों का लागू करना अनुचित गमनता है या निधि ऐसी कियाविधि को अनुपयुक्त समझता है उद्देश्यार्थ प्रायात्मक अधिकारियों के मामले में। ऊपर उल्लिखित मामलों में निम्ननिविदा मामले प्राप्ति का कार्यवाला इस प्रकार लागू किया जाए कि वह ओपचारिक बुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा कियाविधि का पूर्ण सम्बन्ध सीमा तक यथा उपयुक्त पालन करे।

(1) ओपचारिक बुलिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा

(2) अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनात्मक अधिकारियों

(3) एक ही सम्भरक से सीधे ही भ्राती।

खण्ड 1.03 सविकारों की किसी भी और आकार

संविकारों निष्पादित वाम के लिए इकाई सूत्य के या आवेदित मर्दी के या एकमात्र कीमतों के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के सम्बन्ध के आधार पर, प्रशान किए जाने वाले माल या सेवाओं के स्वरूप के अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में कहीं गई संविदा की किसी की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। वास्तविक सूत्य की प्रतिलिपि पर मुद्रयतः आधारित सविदा, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि की स्त्रीकार्य नहीं है।

विस्तृत प्रतियोगिता को बोला देने के लिए, अलग अन्य सविदा ये जिनके लिए ओलियों अमतिल भी जारी हैं, जब भी सुविधाजनक हो इन्हें बड़े आकार की होनी चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर ओलियों आकर्षित कर सकें। दूसरी ओर, यदि तकनीकी भी प्रशासकीय सूत्य में

किसी परियोजना को विशिष्ट प्रकार की मंत्रिदाता में विभक्त करना गम्भीर है और इस प्रकार किया दुया। विभाजित लाभकारी होने की सम्भावना है तो विस्तृत सूत्य से ओपचारिक बुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा को अनुमति प्रदान वरने के लिए लाभप्रद कार्य विभाजित की जाएगी। इनीनियांग उपस्कर और निर्माण के लिए उम्मी तारी द्वारा प्रदान की जाने वाली विदा, (उनकी सावदारी) यदि देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभप्रद कार्य करे तो वे स्वीकार्य हैं।

अनुच्छेद-2

विज्ञापन और पूर्व अर्हताएँ

खण्ड 2.01 विज्ञापन

ओपचारिक बुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन गभी मंत्रियां बोली आमतिल करने के लिए कहीं देश में सामान्य प्रधार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित होनी चाहिए। विज्ञापन के बोली आमतिल करने की प्रतियोगी पात्र सोत देशों के स्थानीय पत्रिनिविदियों को भी तुरन्त प्रेरित की जानी चाहिए।

खण्ड 2.02 बोलो लगाने वालों की पूर्व अर्हताएँ

जिस मामले में निधि बोली लगाने वालों की पूर्व अर्हताओं को आवश्यक समझती है, उसमें निधि बोली लगाने से पूर्व की शर्ती को सामान्यता प्रदान कर सकता है। यह निम्नलिखित वालों का ध्यान में रखने हुए किया जाना चाहिए।

- (1) प्रत्येक पार्टी का ममान कार्य में अनुभव और भूतकार्यान निष्पादन,
- (2) कर्मचारीयण, उपस्कर और संगठन के सम्बन्ध में उसकी सामर्थ्य और
- (3) उसकी आर्थिक स्थिति।

पाल समझे जाने के लिए इच्छा रखने वाले सविदाकारों की मधिल विशिष्टिकरण उपलब्ध कराएँ जाएंगे। यदि पूर्व अर्हताएँ प्रयोग की रही हों तो उन सभी पार्टीयों की बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी जो पात्र पाई गई हैं।

अनुच्छेद-3

बोली के इस्ताबेज

खण्ड 3.01 निधि का सम्बन्ध

बोली लगाने वाले इस्ताबेज निम्नलिखित भावामें होने चाहिए—

“... (कहीं का नम) विवेशी आर्थिक सक्षयोग निधि से पूर्ण करण... येन मे... (परियोजना का नाम) की कीमत के महे ने प्राप्त किया है (आपका उपयुक्त मामलों में “प्राप्तेवन किया है)।”

खण्ड 3.02 बोलो बाण और गारन्टी

बोली बाण या बोली की गारन्टीया साधारण आवश्यकताएँ हैं ऐसिन इनको इनना कठिन नहीं बनाना चाहिए। जिससे कि उचित बोलीकार बोलोम्पाह हो जाए। बोली खुलने के पश्चात् जैसे ही सम्बन्ध आ बोली बाण अथवा गारन्टीया असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए।

खण्ड 3.03 सविदा की शर्तें

सविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किसी भी परिवर्तनों में दी संविदा की शर्ती में कहीं और ठेकेदार या सम्भरक के अधिकार

प्रौढ़ दायित्व और यदि ज्ञानी द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया गया है तो उनके अधिकार और प्राधिकार समृद्ध रूप से परिभाषित होने चाहिए। संविदा की परम्परागत मानामूल शर्तों, जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निर्विवरण विन्दुओं में किया गया है के अन्तिरिक्त परिवर्तनों के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

खण्ड 3. 04 विशिष्टिकरणों की स्पष्टता

जहाँ तक सम्भव हो पूर्ण किए जाने वाले कार्य, सम्भवित किए जाने वाले माल और सेवाओं और सुपुर्देशीया संस्थापन के स्थान को विशिष्टिकरणों में समृद्ध और यथार्थ रूप से घोषित करना चाहिए। अग्रिम विशिष्टिकरणों के भूल विषय के अनुसार होने चाहिए, जहाँ पर ऐसा नहीं होगा वहाँ पर मूल विषय ही प्रधान रहेगा। विशिष्टिकरण में उन मुख्य तत्वों द्वारा धारारों की पहचान होनी चाहिए जिनको बोलियों का मूल्यांकन करते समय और उनकी तुलना करते समय घान में रखा जाएगा इसके अतिरिक्त कोई अन्य सूचना, स्पष्टीकरण, विशिष्टिकरणों में दुई गलतियों को ठीक करना अवश्य उनमें परिवर्तन करते के सम्बन्ध में उन सभी की तुरन्त सूचना भेजी जानी जिन्होंने भूल बोली दर्शवाचेजों के लिए आवेदन किया है। बोली के आमंदण में पात्र स्रोत वेश विशिष्ट होने चाहिए और अपाप्त स्रोत वेशों से अनुदेश आयातों के लिए यदि कोई प्रावधान हो तो वह भी विशिष्ट होना चाहिए। जिन मामलों में निधि अधिकारिक बोली अन्तर्राष्ट्रीय निविश (देखिये खण्ड 1.02) में भिन्न किसानियों के लिए सहमत हो गई है उनको छोड़कर विशिष्टिकरण का इसमें इस प्रकार उल्लेख होना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय बोली नामे वालों की अनुमति और प्रोत्साहन मिले।

खण्ड 3. 05 मानवध

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान आंशिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पर्य कम्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर दिया जाएगा।

खण्ड 3. 06 बाल नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुरुजों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खाग आदायक विशेषाओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन अभ्यास पर अधिरित होने चाहिए और उन्हें एक केवल ज्ञाप्त नाम, सूची संज्ञा या विशेष विनियमों के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पर्यवस्थाओं के प्रमाणों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलनी-जुलनी है और उन विशिष्टिकरण के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं।

खण्ड 3. 07 संविदाओं के अन्तर्गत खर्च

कुक्कि निधि के ज्ञान का उपयोग पात्र स्रोत वेशों के लिए तक में उत्पादित माल के लिए अपाप्त स्रोत वेशों से अनुमति आयात के लिए और पात्र स्रोत वेशों से भेजी गई सेवाओं के लिए किए जाने वाले वित्तदान करने तक ही सीमित है इसलिए संविदा के अन्तर्गत बोली वस्तावेजों में ठेकेदार अधिकार सम्भरक को अपने व्यय नियन्त्रित रखने चाहिए, या अपने विवरण-प्रकारों या बोजकों में अपाप्त स्रोत वेशों में किए गए खर्चों का बोध कराना चाहिए। जिन माल और गोदाओं के लिए निधि वित्तदान करती है उनके भींगांतिक मूल उद्गम और उनके प्रमुख संघटकों से सम्बन्धित सूचना की आदायकता निधि की गांधियीय उद्देश्यों के लिए होती है ठेकेदार अधिकार सम्भरकों को बोली वस्तावेजों में आदायक सूचना भेजनी चाहिए।

खण्ड 3. 08 बोलियों की कीमत जागता

कुक्कि निधि यह जापान येन में बर्गकृत किया गया है, बोली का मूल्य जापान येन में दर्शाया जाना चाहिए लेकिन बोली मूल्य का वह भाग जिसको बोली जागता बोली अहमीयता देता चाहता है उसका वर्णन ज्ञानी की मुद्रा में किया जाना चाहिए।

खण्ड 3. 09 संविदा की कीमत

संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए व्यार्थों कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ज्ञानी के देश में वर्त करेगा ज्ञानी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

खण्ड 3. 10 मूल्य समंजन करिवकार

बोली वस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्षी कीमतों की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है। यदि संविदा के प्रमुख लागत अवश्यकों पर्याप्ति अम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता तो उपयुक्त मामलों में संविदा की कीमतों में समंजन (उत्तर-चावाव) के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली वस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना चाहिए ताकि वही प्रावधान सभी बोलियों में लागू किया जा सके माल की सलाही के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन मिलिल कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्वर सुपुर्देश किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं होती चाहिए। ये मार्ग-निर्वेशन विन्दु उन विभिन्न उपयोगों के परिवर्य का आधारम् सही करती हैं जिनके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

खण्ड 3. 11 अधिग्रंथ भुगतान

खर्च जलाने के लिए संविदा के सपावन पर अधिग्रंथ रूप से किए गए कुल भुगतान का प्रतिशत उचित होना चाहिए। अन्य लिए जाने वाले अधिग्रंथ धन जिसे काम में आने वाले माल की साईट पर सुपुर्देशों के लिए भी बोली वस्तावेजों से स्पष्ट रूप में वर्णित किया जाना चाहिए।

खण्ड 3. 12 गारन्टी, विष्यावत बांड और रोकी रखी धनराशि

नामांकित कार्य के लिए बोली वस्तावेज में गारन्टी के लिए कुछ जामानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेगा। यह जामानत या तो बीक गारन्टी बांड द्वारा दर्शाया निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होती, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में ज्ञानी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उचित जामानती प्रवधि को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारन्टी या भींगांतिक बांड की धनराशि को बोली वस्तावेजों में निरुपित किया जाना चाहिए।

माल की सलाही के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह बालीय होगा कि बीक गारन्टी अधिकार बांड की अपेक्षा गारन्टी निष्यावत के लिए रोकी रखी गई धनराशि का ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोकी रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए यह तो बोली वस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए। लेकिन, यदि बीक गारन्टी अधिकार बांड कुना जाता है तो यह केवल नामांकित धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

खण्ड 3. 13 बीमा

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्मों का बोली वस्तावेजों में संक्षेप में वर्णित होना चाहिए।

खण्ड 3 14 चुकाई जाने वाली क्षति और बोनस प्रावधान

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्देशी में देर होने के कारण फालतू खर्चा, गजम्ब की हानि या अन्य लाभों से तुक्सान होना है तो बोली दस्तवेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से सम्बद्ध प्रावधान शामिल होना चाहिए। टेकेदार द्वारा सविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा उमर्मे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जबकि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो टेकेदार को बोनम देने की भी व्यवस्था की जाए।

खण्ड 3 15 बाध्यकारी परिस्थिति

बोली वस्तु, जो मेरी शामिल की गई सविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबन्धित करते हुए इस सम्बन्ध में वाक्याश होने चाहिए कि सविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को पुरा न करना उस हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवरण स्थितियों (फोर्म बेजप्पेर) के फरवर्त्वरूप हुई है (सविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है ।)

खण्ड 3 16 भाषा की व्याख्या

बोरो दस्तानेज अंग्रेजी मे नैरर फिर जाने चाहिए । यदि बोली दस्तानेजो मे भाग इस्टेमान मे लायी जाए तो दिसे दस्तानेजो के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन-सी भाषा प्रमुख है ।

खण्ड 3 17 मङ्गडों का निपटान

झगड़ी के निराट से सम्बन्धित व्यवस्थाएँ सविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह वास्तवीय है कि व्यवस्थाएँ अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर आवारित होने चाहिए।

अनुच्छेद IV

बोलो खोलना, मल्याँकन और ठेका देना

खण्ड 4 01 बोलियों के आमत्रण और प्रस्तुत करने के बीच का समय

बोली नैतार करने के लिए अनुमित समय अधिकान्तर सविदा की महत्वता और वेकेदारी पर निर्भर करेगा। साधारणत अन्तर्विदीय बोली के लिए कम से कम 45 दिन की स्वीकृति दो जानी चाहिए। जहां पर नामांकित गिरफ्ति कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित बोलीकारों का अपनी बोलिया प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली भाति देखभाल करने के लिए आमतौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए। किन्तु अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से सम्बन्धित परिस्थितियों को ध्यान में रखने होए होता चाहिए।

खण्ड 4 02 बोली खोलने की क्रियाविधि

बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली खालने के लिए तिथि, समय और स्थान की बोली आमवण में घोषित किया जाता चाहिए और सभी बोलियों निर्धारित समय पर खुले ग्राम खोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों का लिना खालने ही लैटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुराध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की तुलना गणित जोर में पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

ਖੱਣਾ 4 04 ਬੋਲਿਪ੍ਰੋ ਕਾਂਸਟਾਈਕਰਣ ਯਾਂ ਤੁਨਮੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ

बोली खुलने के पश्चात् किमी भी बाली बालने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर

कोई प्रभाव न पड़े। कृष्णी किमी भी बोलते बोलते से अपन वाली के विषय म माध्योकरण के लिए कह मत्ता है लेकिन बोलतार को उनसी बोली के बास्तविक एवं मन्त्र परिवर्तन के विषय म नहीं कहता जाता।

ਖੱਡ 4 04 ਗਪਤ ਰਖੋ ਜਾਂਨੇ ਵਾਲੀ ਕਿਧੁਕਿਧੁ

कानून द्वारा यथा प्रवेशित को छोड़कर बोली के खुलने के बाद बाली से सम्बन्धित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से सम्बन्धित रिपोर्टों के बारे में भी उम्म व्यक्ति का जो इन क्रियाविधिया से औपचारिक रूप से सम्बन्धित नहीं है तब तक नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक कि सकन बोलीकार के लिए विविध के निर्णय को घासित नहीं कर दिया जाता है।

खण्ड 4 05 बोलियो की जाँच

बालियों के खुनने के बाद इसका सुनिश्चय कर नेता चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिकलन में विषय सम्बन्धी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेज विलूप्त बोलियों के अनुसार है, क्या आवश्यक जामानती की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित हैं और क्या बोलिया सामान्यतः अन्यथा रूप से मर्ही हैं? यदि बोलिया मूल रूप में विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं है या उसमें अन्यीकृत शर्तें हैं या अन्यथा मूल रूप में बोली सम्बन्धी दस्तावेजों के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक बोनी के मूल्यांकन के लिए और बोलियों के मिलान के लिए नक्तीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

खण्ड 4 06 बोलिकारो की पूर्व योग्यताएँ

पूर्व योग्यताओं की अनुशीलिति में आयातक को चाहिए कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सबद्ध लक्षित क्षेत्रों की रूप से चलाने के लिए धूमता है और धन है जिसकी बोली का काम कम से कम मूल्याकन किया गया है। यदि बोलीकार इन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

खण्ड 4 07 बोलियों का मह्यांकन और मिलान

बोलिया का मूल्याकृत बोली दस्तावेजों में निश्चित नियमों एवं शर्तों के अनुयार होना चाहिए। अधिकारीय गलतियों के लिए समजित बोली की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्यकुशलता एवं क्षमता या फालतु पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीका की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहा तक सभव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टिकृत मानदण्ड के अनुसार स्पष्ट पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए। यदि काई हो तो बोली में शामिल की गई समजन कीमत के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएँ जिनमें मूल्य आका जाता है बोली स्वीकृत होने पर कहणी द्वाग भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना छट्टी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्याकित होना चाहिए और इसका उल्लेख बोलो दस्तावेजों से भी होना चाहिए। ऐसे मूल्याकन में उपयोग के लिए विनियम की दर मरकारी ओंत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर हानी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलिया खुलन के दिन तक उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू हानी चाहिए। ऐसे मामलों में सफल बोली-कार के निर्णय अधिसूचित करने समय विनियम की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

बोली की मूल्याकान और मिलान की रिपोर्ट जिसमें वे विशेष कारण निर्धारित किए गए हैं जिन पर न्यूनतम मूल्याकान मूल्याकान बोली का निर्धारण आधारित है अर्थात् या उसके सलाहकारों द्वाया तैयार की जानी चाहिए।

खण्ड 4. 08 बोलियों को अस्वीकृत करना :

बोली वास्तवजों में सामान्यतया यह व्यवस्था की गई है कि अणी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और नहीं बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनावधि पूर्ण। उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियों आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए। यह उन मामलों को छोड़कर होमा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए भी तब प्रौचित्य देने चाहिए जहां (क) बोलियों, बोली दस्तावेज के प्राप्ताय के अनुसार नहीं है या (ब) अहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो अणी को चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृति सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिस्थोषन पर (या बोलियों के लिए मूल सामंत्रण में भागी गई पर्यवस्थाओं की धनराशि पर) या बोनों पर विचार करें। विशेष स्थितियों में निविधि पर विचार करने के बाद अणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकार के साथ सौदा कर सकता है।

खण्ड 4. 09 संविदा का निर्णय :

संविदा का निर्णय उम बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोसी न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निविधि की गई है और यो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक ग्रन्ति के रूप में विशिष्टिकरण में निविधित पर्यवस्थाओं के लिए या अपनी बोली को परिस्थोषित करने के लिए जिम्मेदारी ले।

बोलियों का विश्लेषण करने के पश्चात बोलियों के विश्लेषण की प्रतियोगी और निर्णय के लिए प्रस्ताव ऐसे प्रस्तावों के लिए कारणों सहित निविधि के अनुसूचन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

अनुच्छेद V

सलाहकारों के उपयोग के लिए मर्ग-वर्णन

खण्ड 5. 01 सलाहकारों की स्वतंत्रता :

निविधि के अन्तर्गत परियोजना के वित्तवान के संबंध में नियुक्त की गई सलाहकार पार्टियों इस दुष्टिकोण से स्वतंत्र होंगी कि उनकी सलाह और आलेख, विशिष्टिकरण और उनके द्वारा धनाएं या निविदा वस्तावेज राष्ट्रीय, वाणिज्यिक अधिकारी और दीप्तियोगिक पक्षपात्र से मुक्त हैं।

सलाहकार इंजीनियर जो कि टेकेवारो अधिकारी विनियोग पार्टियों से मिले हुए है केवल तभी उपयोग में लाए जा सकेंगे जबकि स्वयं और उनके साथी एक ही परियोजना पर किसी भी अन्य क्षमता से कार्य के लिए प्रयोग्य घोषित किए जाएंगे। सलाहकार इंजीनियरों के मामले में जो कि विनियोगिताओं के साथ लगे हुए हैं और गलाहकार सेवाएं प्रदान करते हैं केवल यह सुनिश्चय करने के लिए ही ध्यान नहीं रखा जाएगा कि वह कम्पनी जिसमें सलाहकार संबंधित है परियोजना के किसी भी भाग पर विविध में बोली बोलने के लिए न केवल प्रयोग्य घोषित कर दी जाएगी बल्कि वे विशिष्टिकरण में निष्पक्ष होंगे और उनका प्रतियोगिता के आधार पर पालन किया जाएगा।

खण्ड 5. 02 सलाहकारों का व्यवहार :

गलाहकार पार्टियों के व्यवहार के लिए ग्रौपकारिक प्रतियोगात्मक बोली क्रियाविधियों की आवश्यकता मही है। लेकिन, व्यवहार के दौरान अणी, प्रस्तावित पार्टियां की उचित संख्या पर विचार करेगा जिसमें निविधि द्वारा अधिसूचित पार्टियों भी शामिल होंगी, जिनमें पावर औत देखने वाला उचित तथा स्वतंत्र सेवाएं प्रशान करने की सम्भावना हो सकती है।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण कम से कम तीन पार्टियों तक बढ़ाया जा सकेगा। प्राप्त होने पर प्रस्तावों की पहले गुणात्मक आधार पर तुलना की जानी चाहिए अर्थात् योजना बनाने के संबंध में, अनुसूचियां, नियुक्त किए जाने वाले अपक्रिया का अनुभव और क्षमताएं, दिए गए कार्य के लिए सबसे योग्य समझी गई पार्टी अथवा पार्टियों के चयन के पश्चात् पूर्ण निर्णय पर प्रस्तुत करने के लिए संविदा के मूल्य और अन्य वित्तीय शर्तों पर मानने के लिए बानपीत प्रारम्भ की जानी चाहिए। निधि द्वारा परियोजना की तंयारी और पर्यवेक्षण के लिए यही गई सहायता के लिए अणी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी पहले ही नियुक्त किए गए सलाहकारों के अधिकार नियिका को प्राप्त है।

अनुबन्ध 3

प्राधिकार-पद जारी करने के लिए प्रार्वता-पद

संघीय

विनायक :

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त भंत्रालय,

आधिक कार्य विभाग,

‘यू०सी०ओ० ई०क डिस्ट्रिक्ट, प्रथम मजिल
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई विल्ली-110001

विषय:—1979-80 के सिए येन फैरिंट सं० आर०डी०पी इ/पॉर-
योजना सहायता के प्रस्तावत जापान से.....का
मायात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित य० फैरिंट आर०डी०पी इ(परियोजना सहायता) के
प्रधीन जो कि के मायात के संबंध में.....
.....(बैक का नाम) जो कि वही होना चाहिए जो नीचे (ङ) में
मम्बद्द समुद्रपार संभरक के नाम में साथपत्र बोलने के लिए दिया गया है
को प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित और
प्रस्तुत करते हैं:—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता।

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख
जिस तक वैध है।(ग) प्राप्ति के तरीके—क्या वह सीधे क्या या ग्रौपकारिक खुले
अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि
कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतिस होना चाहिए
कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम क्षक्तीकी प्रस्ताव
के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण।

(ङ) माल का उद्गम देश।

(ज) यदि कोई हो तो पात्र से इतर ओत वेशों से आयातित संघटकों
का प्रतिशत।

(झ) संविदा का कुल अवृक्ष पर निःशुल्क मूल्य (येन में)।

(झ) यदि कोई हो, तो भारतीय ऐजेंट के कमीशन की अन्वराशि
(येन में)।(झ) वास्तविक जनाम पर निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिए
प्राधिकार पत्र मांगा गया है।(झ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं
दिनांक।

(ट) सम्ब्रपार के संभरक का नाम और पता :—

- (1) राष्ट्रिकता।
- (2) पाद स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए शयरों का प्रतिशत।
- (3) प्रतिनिधि की राष्ट्रिकता और/या सम्भरक निवास स्थान।
- (4) उन निवेशकों का प्रतिशत जो पाद स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं।

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।

(ड) सुपुर्दंगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।

(ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय दिय जाने वाले दस्तावेज़ (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)।

(ण) पोतलदान अनुदेश वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिये।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(थ) व्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई हैं, यदि हाँ तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत ओई सी एफ को इसे अधिसूचित किया गया है।

अनुबन्ध-४

प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
संख्या एक
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इण्डिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

बिषय :—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) क्रृपण करार संख्या आई० डी० पी०-५ के अधीन आयात साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को दिए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एवंद्वारा यथा संलग्न और के अनुसार सर्वश्री के नाम में येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक ओई ई० सी० एफ० भारतीय द्रूतावास टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए।

साख पत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपके काष्ठ से किया जाएगा। भुगतान के बाद ओई० सी० एफ० को आवश्यक दस्तावेज़ भेजकर किए गए भुगतान को प्रतिपूर्ती का दावा तत्काल करना चाहिए।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओई० सी० एफ० द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार भारतीय द्रूतावास, टोकियो द्वारा सीधे ही व्याज दिया जाएगा। बैंकों के अन्य खर्चों जिसमें साख-पत्र खोलने, रख-रखाव करने और साख-पत्रों को जारी रखने के लिए खर्च भी शामिल हैं क्योंकि वे भी प्रत्यक्ष दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो विदेशी संभरकों के बैंकों के खर्चों भी विदेशी संभरक को ही देना पड़ेगा और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओई० सी० एफ० से नहीं किया जा सकता।

यह प्राधिकार पत्र सम्ब्रपार संभरकों के नाम में साखपत्र खोलने के लिए है। इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मध्य खोले गए आगे के नए साख-पत्र या साख-पत्र में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार पत्र तक बैंध रहेगा।

भवदीय,

लेखा प्राधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. आयातक को उनके पत्र संख्या दिनांक के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक उनसे निवेदन है/किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इण्डिया, टोकियो बांच से दस्तावेज़ प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन के बराबर रूपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि वे बराबर रूपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8 आई० टी० सी० (पी०एन०)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा कर दी जाती है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी में जमा करनी चाहिए। इस मंत्रालय में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई०टी०सी० (पी०एन०)/68 दिनांक 30-8-68 संख्या 233 आई० टी० सी० (पी० एन०)/68 दिनांक 24-10-1968, संख्या 132-आई०टी० सी० (पी०एन०)/71 दिनांक 5-10-1971, सं० 74 आई० टी० सी० (पी० एन०)/74 दिनांक 31-5-74 और संख्या 103 आई० टी० सी० (पी० एन०)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह “के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज 843 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिस एट्सेक्ट्रा फोम एक्सोड-परचेजिस अन्डर क्रेडिट/लोन एप्रिमेंट अन्डरडिटेलड है” “2.7 विलियन येन क्रोडिट (परियोजना सहायता) सं० आई आई० टी०-सी० 5 फार 1979-80 फोम जापान क्रेडिट्स फोम दि गवर्नरमेंट आफ जापान” है।

जिन मामलों में तुल्य रूपया रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या-132 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनको चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अप्रेण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

पहली मंजिल, यू० सी० ओ० बैंक विलिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली ।

जिस भागले में तुल्य रूपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं. दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शी हुए हो द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएँ उपर्युक्त पंक्ति पर भेजी जानी चाहिए । सभी भागलों में, जमा किए गए तुल्य रूपया का पूरा व्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए ।

समुदायपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हों तो, बैंकिंग खर्चों व्यापार और बैंक आफ इण्डिया, टोकियों बांच के अन्य खर्चों इण्डिया बैंक और बैंक आफ इण्डिया, टोकियों शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएं ।

3. निदेशक, अर्णुण विभाग-2, समुदायपार मार्थिक सहयोग निधि, टेक्समी भूमो विलिंग 4-1, भ्रोहटमेची 1-कोमे चियोडा-अ० टोकियो 100, जापान ।

4. भारतीय दृतावास, टोकियो ।

5. प्रबंर संघिय, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

लेखा प्रधिकारी ।

प्रतुदर्श 5

(ओ० ई० सी० एफ०-एन०सी०-प्रपत्र)

प्रपरिवर्तनीय/साखा-पत्र
(माल के लिए लागू)

दिनांक

सेवा में,

..... यह साखा-पत्र (अहोनी) और विवेशी प्रार्थिक सहयोग निधि के बीच हुए [संभरक का नाम और पता] अर्णुण करार सं. दिनांक के अनुसरण में जारी किया गया है ।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए वर्णनी हुए हो द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साखा-पत्र सं. खोल दिया है जो येन (..... येन कह सकते हैं) की कुल धनराशि में अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ मेजा जाना है ।

हस्ताक्षरित बाणिज्यिक बीजक

कलीन ग्रान बोर्ड, समुदी पोतलदान विल जिनमें दिए गए भावेश का पूरा सेट हों ब्लैक पृष्ठाकृत एवं चिह्नित 'फेट' एवं 'नोटिफाई'

अन्य दस्तावेज जिसमें से तक सदान का सत्यापन दिया गया हो (संविदा संस्था) (वरि कोई हो) के संरभ में माल का संक्षिप्त विवरण आंशिक पोतलदान स्वीकृत है । वाहनात्तरण यदि स्वीकृत है ।

पोतलदान विल जो से बाव की तिथि का नहीं होना चाहिए ।

भावेशी को द्राफ्ट 19 तक भवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी द्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह घंटन होना चाहिए ।

"अपरिवर्तनीय साखा-पत्र संस्था दिनांक 19 के अन्तर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ संस्था (संस्थाएं) (यदि कोई हो)" यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है ।

हम एतद्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसको शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी द्राफ्ट प्रस्तुत करते पर और आदेशी की दस्तावेजों की सुनुदर्शी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे ।

जब तक अन्यथाकृप से विस्तारपूर्वक न बताया जाए यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एण्ड प्रैविट्स फार डाक्मेन्ट्स (1974 रिवीजन), इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, प्रिलेकेशन नं० 290" के प्रधीन है ।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विवेष अनुदेश :

उपर्युक्त प्रकृत करार के अन्तर्गत जारी किए गए वचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विवेशी आंशिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुए होनी की धनराशि को सौदा देंगे ।

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हमें द्राफ्ट्स और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र भवश्य सेजें की शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा को मेज दिए गए हैं ।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्च संभरक के लिए के लिए हैं ।

भवदीय,

(.....)

बाणिज्यिक बैंक

हारा

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान शर्तें

यह भुगतान हमारी साखा-पत्र सं. का भविष्य प्राप्त है

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि येन जो कि कुल संविदा मूल्य के प्रतिशत है

आपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि येन जो कि कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत है

आपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख

3. पोतलदान दस्तावेजों के महे भुगतान

धनराशि येन संविदा जो कुल मूल्य का प्रतिशत है

टिप्पणी:— पोतलदान दस्तावेजों के महे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है ।

मैं, प्रधोहम्माधीरी, प्रतिनिधि (अर्थी) एम्बेड्डर
प्रीर के बीच हुए समझौता से
दिनांक में निहित अंग-
तान की गती के अनुसार ममुद्दपार आधिक सहायता निधि द्वारा ...
की धनराशि (..... येन क्रेडिट) प्राप्त करने
के लिए एक नियावत विवरण आगे करता हूँ।

(अर्थी)

द्वारा

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश—

वास्तविक नियावत का विवरण इसमें सकान पत्र में वर्णिया जाएगा।

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 37—ITC(PN)/80

New Delhi, the 1st October, 1980

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Licensing conditions in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of Y 2.7 Billion extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECAF).

The terms and conditions governing the issuance of import licences in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of Y 2.7 Billion for Telecommunication Project (II) extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECAF) as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

[Issued from F. No. IPC/23/3/80]

Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No. 37—
ITC(PN)/80

New Delhi, the 1st October, 1980

Licensing Conditions in Respect of Imports of Goods and Services under the Yen Credit of Y 2.7 Billion for Telecommunication Project (II) Extended by the Overseas Economic Co-operation Fund (OECAF)

Section I—General Conditions :

I(i) The Yen Credit of Y 2.7 billion extended by the Overseas Economic Co-operation Fund of Japan (OECAF) for financing the import requirements of the Telecommunication Project of the DGP&T is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

I(ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Y 3,000 million, (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No 78-ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-p. 5". The first and second suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to D.G.P&T, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(iii) Import Licence(s) can be issued only in favour of DGP&T on CIF basis.

I(iv) Depending on the convenience of DGP&T more than one import licence may be issued under this credit but the total value must not exceed Y 3,000 million (CIF) as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by DGP&T, be granted upto 31-12-84. Request for further extension, if any should be referred to the Department of Economic Affairs (Japan Section).

I(vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I(vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agents commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are NOT acceptable.

I(ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facilities of letter of authority for the establishment of letter of credit acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I(x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on each basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :

“..... Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of”.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-84.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order

and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be born in mind :—

- Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.
- Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.
- Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :—

- Where the importer has convincing reasons or maintaining a reasonable standardisation of his equipment.
- Where the number of qualified suppliers is limited.
- Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.
- Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure inapplicable, e.g., in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

- Formal Selective International Tendering.
- Informal International Competitive Procurement.
- Direct Purchases from a single supplier.

DGP&T should prepare a detailed report on the evaluation and comparison of bids setting forth the specific reasons/justifications on which the lowest evaluated bid is based and submit it in triplicate along with bid analysis statements/sheets supported by documentary evidences, if any to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section), North Block, New Delhi who will obtain the necessary approval of the same from the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF). It should be noted that purchase contracts will be notified by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Japan Section) to the O.E.C.F. only after obtaining the OECF approval of the report etc.

II(iv) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OFCF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 5 for 1979-80 the details of which are given in Section VI below.

II(v) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vi) Eligibility of Supplier

The Suppliers shall be nationals of the eligible source countries, or juridical persons governed substantially by national of the eligible source countries, satisfying the following conditions :

- a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries.

(b) that a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source country; and

(c) such juridical persons have been registered in the eligible source countries.

II(vii) Declaration in Contract

The following statements of eligibility by the supplier shall be added to each contract.

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in _____ (eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula :

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100\%$$

and

"I, the undersigned, hereby certify that _____ (Name of company) has been incorporated and registered in _____ (name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries."

II(viii) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30%) on an item-by-item basis in accordance with the following formulae ;

$$\frac{\text{IMPORTED CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 8th May, 1980 concerning the Yen Credit No. ID-P.5 (Project Aid) for Tele-communication Project (II) and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P.5 dated 8th May, 1980 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The Overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II(vii)

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF

IV(i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both DGP&T and Overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects together with two photo of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

(ii) The above procedure will also apply to all contract—amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

(iii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen Credit No. JP-P.5 (Project Aid) for Telecommunication Project (ii).

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure

V (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance Department of Economic Affairs, Japan Section, DGP&T and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the DGP&T should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of a letter of authorisation. The CAA&A will issue a letter of authorisations in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would *in so far* apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of the goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) All charges on account of opening, maintenance and on the operation of the letter of credit will be to the account of Overseas Suppliers. Bank of India, Tokyo will, therefore, recover all these charges from the Suppliers' Bank. charges for handling and negotiating the documents and other incidentals will also be borne by the suppliers.

For the time lag between the dates of payment of the F.O.B. cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF the B.O.I. will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (M/o Finance) on 25-3-1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest payment by the Embassy of India in Japan will be recovered from the P&T Department (vide Section VI(iv) infra).

Section VI—Responsibility for rupee deposit

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of DGP&T as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the DGP&T make the rupee deposits at RBI, New Delhi or S.B.I. This

Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. The rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas supplier are to be deposited into Government of India Account in the manner prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)/74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances—843-Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/ Loan Agreements Loans from the Government of Japan-2.7 billion Yen Credit No. ID-P.5 for Telecommunication Project (II)." The provisions regarding calculation and deposit of interest charges mentioned in the above said Public notice of 31-5-1974 will, however, not be applicable, as no interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government departments.

VI(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-68, No. 132-ITC (PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

VI(iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India. Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury Challans :—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

The rupee equivalents of Yen payments on account of interest charges etc., made by Embassy of India, Tokyo, to the BOI, Tokyo will also be calculated in the manner laid down in para VI(i) of Section VI above and deposited in favour of the Principal Accounts Officers, Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA&A will be issuing suitable advices.

Section VIII—Miscellaneous provisions

VIII(i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened, regarding shipment and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII(iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VIII(iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P.5 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VIII(v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII(vi) List of Annexures

Annexure I—List of eligible source countries.

Annexure II—Broad Guidelines for Procurement.

Annexure III—Request for issue of Letter of Authority.

Annexure IV—Form of Letter of Authority.

Annexure V—Form of Letter of Credit (Applicable to Physical Imports).

Annexure VI Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

ANNEXURE I**List of Eligible Source Countries****A. Developing Countries and Territories****(a) Non-OPEC Developing Countries :****I. AFRICA, North of Sahara :**

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara :

Angola
Botswana
Burundi
Cameroun
Capo Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomey
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast

Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Mozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep (2)
Sao Tomo and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. AMERICA, North and Central

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago
West Indies (Br.) n.i.c.
(a) Associated States (3)
(b) Dependencies (4)

IV. AMERICA, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following Islands : Ascension, Tristan da Inaccessible, Nightingale, Gough.

(3) Main islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(4) Main islands : Montserrat, Cayman, Turks, and Caicos, and British Virgin Islands.

Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East :

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (1)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (2)

Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

(a2) Member or Association Countries of OPEC :

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

VI. ASIA, South

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East :

Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of
Laos
Macao
Malaysia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA

Cook Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (3)
Nauru
New Calendonia
New Hebrides (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (4)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. EUROPE :

Cyprus
Gibraltar
Greece

ANNEXURE II
Guidelines for Procurement under the Loan

TABLE OF CONTENTS

Article Number	Title	Page No.
Article I. General		
Section 1.01	Introduction	.
Section 1.02	Procedures Other than Formal Open International Tendering	.
Section 1.03	Type and Size of Contracts	.
Article II. Advertising and Prequalification		
Section 2.01	Advertising	.
Section 2.02	Prequalification of Bidders	.
Article III. Bidding Documents		
Section 3.01	References to the Fund	.
Section 3.02	Bid Bonds or Guarantees	.
Section 3.03	Conditions of Contract	.
Section 3.04	Clarity of Specifications	.
Section 3.05	Standards	.
Section 3.06	Use of Brand Names	.
Section 3.07	Expenditures under Contracts	.
Section 3.08	Pricing of Bids	.
Section 3.09	Contract Price	.
Section 3.10	Price Adjustment Clauses	.
Section 3.11	Advance Payments	.
Section 3.12	Guarantees, Performance Bonds and Retention Money	.
Section 3.13	Insurance	.
Section 3.14	Liquidated Damage and Bonus Clauses	.
Section 3.15	Force Majeure	.
Section 3.16	Language Interpretation	.
Section 3.17	Settlement of Disputes	.
Article IV. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract		
Section 4.01	Time Interval between Invitation and Submission of Bids	.

(1) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.

(2) Including Aden and various sultanates and emirates.

(3) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, The Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(4) Trust Territory of the Pacific Islands: Caroline Islands, Marshall Islands, and Micronesia Islands (except Guam).

Section 4.02 Bid Opening Procedures	.
Section 4.03 Clarification or Alteration of Bids	.
Section 4.04 Procedures to be Confidential	.
Section 4.05 Examination of Bids	.
Section 4.06 Postqualification of Bidders	.
Section 4.07 Evaluation and Comparison of Bids	.
Section 4.08 Rejection of Bids	.
Section 4.09 Award of Contract	.
Article V Guidelines for Use of Consultants	
Section 5.01 Independence of Consultants	.
Section 5.02 Selection of Consultants	.
Attachment : Eligible Source Countries	

Guidelines for procurement under the Loan

ARTICLE I

GENERAL

Section 1.01 Introduction

(a) These Guidelines set forth the rules which THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (hereinafter called "the Fund") generally applies to the procurement of goods and services for a development project which the Fund finances in whole or in part by its loan.

(b) The proceeds of the Fund's loan are required to be used with due attention to considerations of economy, efficiency and non-discrimination among countries which are eligible for procurement of the above-mentioned goods and services (such countries are hereinafter called "the eligible source countries"). The Fund considers that in most cases formal open international tendering is the best method for achieving the economical and efficient procurement of the goods and services required for the development projects it finances. The Fund therefore normally requires its borrowers to obtain goods and services through formal open international tendering.

(c) The application of these Guidelines to a particular project financed by the Fund, the extent to which bidding documents and procurement procedures are subject to review by the Fund to ensure conformity with these Guidelines, eligible source countries and provisions for permissible imports from non-eligible source countries shall be stipulated in the contractual documents for the loan extended by the Fund for that project.

(d) The ultimate responsibility for the procurement of goods and services on any projects rests with the owner of the project. Since the owner is usually also the borrower, the term borrower has been used in these Guidelines to refer to the owner as well. The rights and obligations of the borrower vis a vis bidders for goods and services to be furnished for the project are governed by the bidding documents issued by the borrower and not by these Guidelines, which are concerned only with the relationship between the borrower and the Fund.

Section 1.02. Procedures other than Formal Open International Tendering.

There may be special circumstances in which formal open international tendering may not be appropriate and the Fund may accept alternative procedures in cases of following :

- Where the borrower has convincing reasons for maintaining a reasonable standardization of his equipment.
- Where the number of qualified suppliers is limited, e.g. of spare parts for existing equipment.
- Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested, or that the advantages of formal open international tendering would be outweighed by the administrative burden involved.
- Where, in addition to the cases (a), (b) and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedures inapplicable for example in case of emergency procurement.

In the above mentioned cases the following procurement formulas may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

- Formal Selective International Tendering
- Informal International Competitive Procurement
- Direct Purchases from a Single Supplier

Section 1.03. Type and Size of Contracts

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items applied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable to the Fund except in exceptional circumstances.

In order to foster widespread competition, individual contracts for which bids are invited shall, whenever feasible, be of a size large enough to attract bids on an international basis. On the other hand, if it is technically and administratively possible to divide a project into contracts of a specialized character and such division is likely to be advantageous and to allow broader formal open international tendering the project shall be so divided.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantage for the borrower country.

ARTICLE II

ADVERTISING AND PREQUALIFICATION

Section 2.01. Advertising

On all contracts subject to formal open international tendering invitations to bid should be advertised in at least one newspaper of general circulation in the borrower's country. Copies of the invitation to bid for the advertisement should also be transmitted promptly to local representatives of the eligible source countries.

Section 2.02. Prequalification of Bidders

In case the Fund recognises necessity of prequalification of bidders, the Fund requires the use of prequalification. It should be done taking into account (i) the experience and past performance of each firm on similar work, (ii) its capabilities with respect to personnel, equipment and plant, and (iii) its financial positions. Abbreviated specifications shall be made available to contractors desiring to be considered for qualification. When prequalification is employed, all firms which are found to be qualified shall be permitted to bid.

ARTICLE III

BIDDING DOCUMENTS

Section 3.01. References to the Fund

Bidding documents should refer to the following language :

".....(name of borrower) has received (or in appropriate cases 'has applied for') a loan from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in.....towards the cost of (name of project)."

Section 3.02. Bid Bonds or Guarantees

Bid bonds or bidding guarantees are usual requirement, but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid Bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

Section 3.03. Conditions of Contract

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the borrower and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the borrower, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

Section 3.04. Clarity of Specifications

Specifications should set forth clearly and precisely as possible the work to be accomplished, the goods and services to be supplied and the place of delivery or installation. The drawings should be consistent with the text of the specifications; where they are not, the text shall govern. The specifications should identify the main factors or bases which will be taken into account in devaluating and comparing bids. Any additional information, clarification, correction of errors or alterations of specifications shall be sent promptly to all those who had requested the original bidding documents. Invitations to bid should contain an indication of the eligible source countries and any provision for permissible imports from non-eligible source countries.

Except where the Fund has agreed to procedures other than formal open international tendering (see Section 1.02) the specifications should be so worded as to permit and encourage the widest possible international bidding.

Section 3.05. Standards

If national standards to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that goods meeting Japan Industrial Standard or other international accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

Section 3.06. Use of Brand Names

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of a specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative goods which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

Section 3.07. Expenditures under Contracts

As the use of the Fund's loan is limited to financing expenditures for goods produced in the territories of the eligible source countries, permissible imports from non-eligible source countries and services supplied from the eligible source countries, the bidding documents should require the contractor or supplier to limit his expenditures under the contract accordingly or to identify expenditures in non-eligible source countries in his statements or invoices.

For statistical purposes the Fund requires information concerning their geographical origin of the goods and services it finances and of their major components. The bidding documents should require the contractor or supplier to furnish the necessary information.

Section 3.08. Pricing of Bids

As the Fund's loan is denominated in Japanese Yen, the bid price should be stated in Japanese Yen provided, however, that for the portion of the bid price which the bidder expects to spend in the borrower's country such portion should be stated in the borrower's currency.

Section 3.09. Contract Price

The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

Section 3.10. Price Adjustment Clauses

Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

In appropriate cases, provision should be made for adjustment (upwards or downwards) in the contract prices in the event changes occur in prices of the major cost constituents of the contract such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents so that the same provisions will apply to all bids.

A ceiling of prices adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

Section 3.11. Advance Payments

The percentage of the total payment to be made in advance from effectuation of the contract for mobilization expenses should be reasonable. Other advances to be made, as for example for materials delivered to the site for incorporation in the works, should also be clearly described in the bidding documents.

Section 3.12. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

Section 3.13. Insurance

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

Section 3.14. Liquidated Damage and Bonus Clauses

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

Section 3.15. Force Majeure

The conditions of contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate stipulating that failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of contract).

Section 3.16. Language Interpretation

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, Eng-

lish should be added to the such documents and it is required to specify which is governing.

Section 3.17. Settlement of Disputes

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of contract. It is appropriate that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which has been prepared by International Chamber of Commerce.

ARTICLE IV

Bid Opening, Evaluation and Award of Contract

Section 4.01. Time Interval between Invitation and Submission of Bids

The time allowed or preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 45 days should be allowed for international bidding. Where large civil works are involved, generally not less than 90 days should be allowed to enable prospective bidders to conduct investigations at the site before submitting their bids. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each project.

Section 4.02. Bid Opening procedures

The date, hour and place for latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and total amount of each bid and of any alternative bids if they have been requested or permitted should be read aloud and recorded.

Section 4.03. Clarifications or Alteration of Bids

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The borrower may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask bidder to change the substance or price of his bid.

Section 4.04. Procedures to be Confidential

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning awards should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

Section 4.05. Examination of bids

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

Section 4.06. Postqualification of Bidders

In the absence of prequalification, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

Section 4.07. Evaluation and comparison of Bids

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors, other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should

be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of the currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

A detailed report on the evaluation and comparison of bids setting forth the specific reasons on which the determination of the lowest evaluated bid is based should be prepared by the borrower or by its consultants.

Section 4.08. Rejection of Bids

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the cost estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b) there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revisions of the specifications or modification in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

Section 4.09. Award of Contract

The award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities or work not stipulated in the specifications or to modify his bid.

After bids have been analyzed, copies of the analysis of bids and proposals for awards, together with the reasons for such proposals, shall be submitted to the Fund for approval.

ARTICLE V

Guidelines for the Use of Consultants

Section 5.01. Independence of Consultants

Consultant firms employed in relation to a project financed under the Funds shall be independent in the sense that their advice and the designs, specifications and tender documents prepared by them shall be free of national, commercial or industrial bias.

Consulting engineers who are associated with contracting or manufacturing firms shall be used only if they disqualify themselves and their associates for work in any other capacity on the same project. In the case of consulting engineers who are affiliates of manufacturers offering consulting services steps shall be taken not only to ensure that the company to which the consultant is affiliated will be disqualified from future bidding on any part of the project, but also that specifications will be impartial and can be complied with on a competitive basis.

Section 5.02. Selection of Consultants

Formal competitive bidding procedures are not required for the selection of consulting firms. However, in the process of selection the borrower shall consider a reasonable

number of prospective firms, including those notified by the Fund, which can be expected to render competent and independent services from the eligible source countries. Invitations to submit proposals shall be extended to at least three firms. Proposals, when received, it should first be qualitatively compared, i.e., with respect to plans of approach, schedules, experience and capabilities of personnel to be assigned; after selection of a firm or firms considered to be best qualified for the assignment has been made, negotiations to agree upon the price and other financial terms of the contract should be opened so as to reach the final decision. The Fund reserves the right to approve the choice of the consultant to be employed or already employed by the borrower for the preparation and supervision of the project financed by the Fund.

ANNEXURE III

Request for issue of the letter of authority

No. Date :

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
U.C.O., Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Sub :—Import of *from Japan under the Yen Credit No. ID-P5 (Project Aid) for 1979-80.*

Sir,

In connection with the import of from under the above mentioned Yen Credit No. ID-P5 (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the (name of the Bank) which should be the same as given in (a) below for opening a letter of credit in favour of the overseas supplier concerned).

- (a) Name and Address of the Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in Yen).
- (h) Amount of Indian agents commission in (Yen), if any.
- (i) Net FOB value (In Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with Overseas suppliers.
- (k) Name and Address of the Overseas Supplier :
 - (i) Nationality.
 - (ii) Percentage of the shares held by Nationals of the eligible source countries.
 - (iii) Nationality of the representatives and/or President of the Supplier.
 - (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries.

- (l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries.
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the importer's bank in India.
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the O.E.C.F.

ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch
Tokyo (Japan).

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No. ID-P5—Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25-3-1980 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen favouring M/s. as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank; to the OECF Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interest as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the Overseas Suppliers and hence not payable by the importer and may therefore be recovered from the Suppliers directly. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto _____.

Yours faithfully,
Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer _____ with reference to their letter No. _____ dated _____.

2. Importers' Banker _____. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-6-68, 233-JTC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements—Loans from the Government of Japan—27 billion Yen Credit (Project Aid) No. ID-P.5 for 1979-80".

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below along with a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India, Tokyo/Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

ANNEXURE V

Form OECF-LCT

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for goods)

To _____ Date : _____

(Name and address of the Supplier)

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. _____.

dated _____
between (Borrower) and the Overseas Economic Co-operation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of _____ for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of _____ (Say Yen _____) available by your draft at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :

Signed commercial invoice in

Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight" and "Notify" _____ Other documents evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. _____ (if any) from _____ to _____. Partial shipments are permitted. Transhipment is permitted. Bills of lading must be dated not later than _____ Drafts must be presented for negotiation not later than.

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under _____" _____ irrevocable credit No. _____, dated _____ and Import Reference No. (s) _____ (if any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Bochure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from the Overseas Economic Cooperation Fund in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been air-mailed direct to _____.

3. All banking charges under this credit are for the account of suppliers.

Yours faithfully,
(a commercial bank)
By _____
(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____.

I. Initial Payment :

Amount : _____
being % of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount :
being % of the total
contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount :
being % of the total
contract price.Note : This attached sheet is not required in case of full payment
against shipping documents.ANNEXURE VI
Form OECF-LC IIIrrevocable Letter of Credit
(Applicable for Services)

Date :

To

_____This Letter of Credit has
been issued pursuant to
Loan Agreement No.—
dated—, between
(Borrower) and The
Overseas Economic Co-
operation Fund.(Name and address
of the Supplier)

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable
credit No. _____ in your favour for account of _____
for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of
Y _____ (Say Yen _____) available by
beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn
on us.To be accompanied by the required documents, in accordance
with the Payment Schedule attached hereto, concerning
(Contract No. with regard to
Project). Drafts must be presented for negotiation not later
thanAll drafts and documents must be marked "Drawn under
irrevocable credit No. _____ dated _____".
This credit is not transferable.We hereby undertake that all drafts drawn under and in
compliance with the terms of the credit shall be duly honored
on due presentation and delivery of document to the
drawee.Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to
"Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
(1974 Revision), International Chamber of Commerce Bro-
chure No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance
issued by (Borrower or its designated authority) in accordance
with the form attached hereto, payment(s) under
this credit must be made in accordance with the Payment
Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of
the initial payments, the beneficiary's Statement is required
instead of the above-mentioned Statement of Performance.2. After obtaining the reimbursement for our payment from
The Overseas Economic Cooperation Fund in accordancewith the provisions of the Letter of Commitment issued there-
by under the above-mentioned Loan Agreement, we under-
take to remit the amount of the drafts in accordance with
the instructions issued by the negotiating bank.3. A copy of the document as mentioned in item 1 above
the drafts shall be sent to us immediately after the receipt
thereof.4. All banking charges under this credit are for the ac-
count of the suppliers.

Yours faithfully,

(a commercial bank)

By : _____

(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our
Letter of Credit No.

I. Initial Payment

Amount :
being % of the total
contract price.

Required documents : beneficiary's Statement

Latest presentation date :

II. Progress Payment

Aggregate amount :
being % of the total con-
tract price to be
paid as follows :Amount due
Latest presentation
date
1st Instalment :
2nd Instalment :Required document : a copy of Statement of Performance
issued by (Borrower or its designated
authority), a form of which is attached
hereto.

STATEMENT OF PERFORMANCE

Date :

Ref. No.

To

.....

.....

(Name and address of the Supplier)

Re : Letter of Credit No. dated
issued by
for in favour of
..... concerning Project
under Loan Agreement No.I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issued
a Statement of Performance to entitle to receive
the sum of (Yen only)
from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND
in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract
No. dated between
..... and
.....

(Borrower)

By :
(Authorized Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the
sheet attached hereto.

सार्वजनिक सूचना सं० 38—प्राईटीसी(पीएम) 80

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1980

विषय :— भवीत 1980—मार्च 1981 के लिए आयात नीति ।

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 9—प्राईटी सी (पी एन) /80 वितांक 15 अप्रैल, 1980 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1980—मार्च 1981 की आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उक्त आयात नीति में नीचे निविष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्न-लिखित संशोधन किए गए समझे जाएंगे :—

क्रम आयात नीति संदर्भ	संशोधन				
	सं० 1980-81 की पृष्ठ संख्या	1	2	3	4
1. 24 अध्याय 15— नियंत्रित उपबन्ध	विष्वामान पैरा 3 के बाद निम्न-लिखित नवा पैरा जोड़ा जाएगा :— “ (19) गैस सिलेन्डरों का आयात 3-क (1) गैस सिलेन्डरों के आयात के लिए आवेदन पत्रों पर मुख्य नियंत्रक आयात नियंत्रित द्वारा मूल्य को ध्यान में न रखते हुए विचार किया जाएगा। आवेदन पत्र पूर्णीगत माल के आयात के लिए निर्धारित श्रपति में ऐसे जाने चाहिए। 2) आवेदन पत्रों पर देसी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के आधार पर विचार किया जाएगा। मुख्य नियंत्रक आयात नियंत्रित, नई विल्ली शास्त्रीय मंत्रालय और संबद्ध तकनीकी प्राधिकारियों के परामर्श से उपयुक्त मार्गनिर्देशन विद्युत बनायेंगे जिससे कि आयात की अनुमति उसी सीमा तक ; जो सके जिस सीमा तक देसी औतों से मांग की पूर्ति न हो सकती हो। (3) एल पी बी सिलेन्डरों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी। (4) चिकित्सा गैस सिलेन्डरों के आयात की अनुमति वास्तविक उपयोक्ताओं की पूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए दी जाएगी। (5) हाई प्रेशर सिलेन्डरों के आयात की अनुमति भी वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना				

1	2	3	4
2. 47 परिषिष्ट 1, प्रविष्टि सं० 6 (15)	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।		
3. 82 परिषिष्ट 5, प्रविष्टि सं० 140 कि (4)—हाई म्यूथ ग्लास फाट- वर प्रैक्टिक और रॉबिम।	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।		
4. 87 परिषिष्ट 5 प्रविष्टि सं० 389	यह प्रविष्टि निम्नलिखित अनुमान पड़ने के लिए संशोधित की जाएगी :— “पीकल और कासे इलेक्ट्रोड्स, छड़ियां/तार।”		
5. 87 परिषिष्ट 5, प्रविष्टि सं० 409	यह प्रविष्टि हटा दी जाएगी।		
6. 87 परिषिष्ट 5 प्रविष्टि सं० 486 (4)	विष्वामान विवरण निम्नलिखित अनुसार पड़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :— “कलिंग ऐपेसिटर्स (पावर लाइट उपस्कर के संबंधक (1))”		
7. 89 परिषिष्ट 5 प्रविष्टि सं० 486 (5) (1)	विष्वामान विवरण निम्नलिखित अनुसार पड़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :— “10000 एम एफ बी मूल्य तक प्रधिकतम 50 बी और 50 बी से प्रधिक और 450 बी तक के रेटिंग के 2000 एम एफ बी मूल्य के रेटिंग के इलेक्ट्रोलिटिक ऐपेसिटर्स।”		

[मिसिल सं० प्राईटीसी/3/9/80 से जारी]

मणि नारायण स्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात नियंत्रित

PUBLIC NOTICE NO. 38—ITC(PN)/80

New Delhi, the 1st October, 1980

Subject : Import Policy for April 1980—March 1981.

Attention is invited to Import Policy for April 1980—March 1981 published under the Department of Commerce Public Notice No. 9—ITC(PN)/80 dated the 15th April, 1980.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the said Import Policy at the appropriate places indicated below :

S. No. Import Policy, 1980-81	Page No. of Reference	Amendments			
		1	2	3	
1. 24	Chapter 15- Miscellaneous Provisions.	After the existing para 111, the following new para shall be added :— "(xix) Import of Gas Cylinders III-A. (1) Applications for import gas cylinders will be considered by Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, irrespective of the value involved. The applications should be made in the form prescribed for import of Capital Goods. (2) Applications will be considered, on merits, having regard to indigenous production. The CCI&E New Delhi will formulate suitable guidelines in consultation with the administrative Ministry and the technical authorities concerned so that import is allowed to the extent the demand can not be met from the indigenous sources. (3) Import of LPG cylinders will not be allowed. (4) Import of medical gas cylinders will be allowed to meet the full requirement of Actual Users. (5) Import of high pressure cylinders will also be allowed as spares to Actual	4		

1	2	3	4
2. 47	Appendix 1, Entry No. 6(15)	This Entry shall be deleted.	
3. 82	Appendix 5, Entry No. 140A (iv)—High Strength glass fibre fabric and rovings	This entry shall be deleted.	
4. 87	Appendix 5, Entry No. 389	This entry shall be amended to read as under : "Brass and bronze electrodes, rods/wires."	
5. 87	Appendix 5, Entry No. 409	This entry shall be deleted.	
6. 89	Appendix 5, Entry No. 486(4)	The existing description shall be amended to read as under :— "Coupling capacitors (components of power-line equipment)."	
7. 89	Appendix 5, Entry No. 486(5)(i)	The existing description shall be amended to read as under :— "Electrolytic capacitors of rating not exceeding 50V with value upto 10,000 mfd., and above 50 V and upto 450V with value 2,000 mfd."	

[Issued from file No. IPC/3/9/80]
MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports & Exports

